



पंचदश

बिहार विधान-सभा

पंचम सत्र

अल्प-सूचित प्रश्न

वर्ग-4

11 फाल्गुन, 1933 (ब०)

बृहस्पतिवार, 11/12/12

01 मार्च, 2012 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या—10

(1) नगर विकास एवं धावास विभाग	01
(2) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	03
(3) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	02
(4) पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	02
(5) कृषि विभाग	02

कुल योग .. 10

पदाधिकारियों पर कार्रवाई

15. श्री अखतरुल इमान--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में 1170 रु0 प्रति क्वींटल गेहूँ की दर से 10.50 लाख मेट्रिक टन गेहूँ समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि क्रय अवधि 15 जुलाई, 2011 समाप्त हो जाने तक संबंधित एजेंसियों तथा उनके पदाधिकारियों द्वारा केवल 5.56 लाख मेट्रिक टन गेहूँ समर्थन मूल्य पर खरीद किया जा सका तथा शेष गेहूँ किसान 700-800 रुपये प्रति क्वींटल बेचने पर विवश हो गए जिससे उन्हें भारी आर्थिक क्षति हुई है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार गेहूँ नहीं खरीदने वाले एजेंसियों तथा उनके पदाधिकारियों पर कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गुणवत्ता की जाँच

16. डॉ० अच्युतानन्द--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाधार-पत्र में दिनांक 19 जनवरी, 2012 को प्रकाशित शीर्षक "स्वच्छ जल योजनाओं की रफ्तार धीमी" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में पूरे राज्य में 60 हजार चापाकल गाड़े गए हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि कम गुणवत्ता वाले चापाकलों के गाड़ने के कारण उपरोक्त 60 हजार चापाकलों में से 6 महीने में ही अधिकतर चापाकल खराब हो गए हैं;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 2010-11 में गाड़े गए चापाकलों की गुणवत्ता की जाँच कराते हुए खराब चापाकलों को चालू करने की कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

एंटो रेबिज सुई उपलब्ध कराना

17. श्री सतीश कुमार--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पालतु मवेशियों को कुत्ता के काटने पर उसके प्राणरक्षार्थ मनुष्यों की ही तरह एंटो रेबिज की सुई दी जाती है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के किसी भी पशु चिकित्सालय में मवेशियों के प्राणरक्षार्थ एंटो रेबिज की सुई उपलब्ध नहीं है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी पशु चिकित्सालयों में एंटो रेबिज की सुई उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

योजनाओं को समय पर पूरा करना

18. श्री विनोद नारायण झा--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में शहरी जलापूर्ति योजना के तहत कुल 38 योजना स्वीकृत है;

(2) क्या यह बात सही है कि 31 मार्च, 2012 तक उक्त सभी योजनाओं का क्रियान्वयन का लक्ष्य रखा गया था, परन्तु अभीतक मात्र 40 फिसदी लक्ष्य ही पूरा हुआ है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इन योजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

19. डॉ० अच्युतानन्द--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 11 अगस्त, 2011 को प्रकाशित "आरोपों के घेरे में 300 इंजीनियर" शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के 141 कार्यपालक अभियंताओं एवं सहायक अभियंताओं, 36 मुख्य एवं अधीक्षण अभियंताओं, 67 कनिष्ठ अभियंताओं के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की जांच विगत 3 वर्षों से लम्बित है;

(2) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सभी पदाधिकारियों के विरुद्ध त्वरित विभागीय जांच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अनियमितता की जांच

20. श्री राजेश्वर राज--दिनांक 30 जनवरी, 2012 को हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित शीर्षक "किसानों की धान की खरीदारी नहीं" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिला एस०एफ०सी० प्रबंधकों को किसानों से सीधे धान की अधिप्राप्ति करना है;

(2) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के बिक्रमगंज, काराकाट, सईली एवं अन्य संचालित क्रय केन्द्रों पर स्थानीय अधिकारियों द्वारा अनियमितता चरते जाने के कारण किसानों की धान क्रय अवरुद्ध है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों से सीधे धान की अधिप्राप्ति करने एवं चरती गयी अनियमितता की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

लक्ष्य पूरा नहीं करने का औचित्य

21. श्री मंजीत कुमार सिंह--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 10 फरवरी, 2012 में "कृषि यंत्रों की खरीद में 65 प्रतिशत ही वित्तीय उपलब्धि" प्रकाशित शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में कृषि यांत्रिकरण में जनवरी माह तक 235 करोड़ 87 लाख 11 हजार रुपये व्यय के लक्ष्य के विरुद्ध 154 करोड़ 99 लाख 2 हजार रुपये ही व्यय हुए;

(2) क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला में 19.70 प्रतिशत, अरवल जिला में 35.87 प्रतिशत, सुपौल में 41.87 प्रतिशत, भागलपुर जिला में 44.69 प्रतिशत ही कृषि यांत्रिकरण राशि खर्च हुई, जिससे कृषि यंत्रों की खरीद का लाभ किसान को नहीं मिल सका है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार लक्ष्य के अनुरूप खर्च नहीं करने का क्या औचित्य है ?

लक्ष्य को पूरा करना

22. श्री संजय सिंह (टाडगार)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 15 जनवरी, 2012 को प्रकाशित "12 शहरों में जलापूर्ति योजना सुस्त" शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य योजना के अन्तर्गत 33 और 12वें वित्त आयोग के तहत पांच शहरी जलापूर्ति योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी थी;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त योजना के तहत गया, डिहरी, किशनगंज, बिहारसरीफ, कटिहार, दानापुर, मोतिहारी, दरभंगा, छपरा जिलों में कार्य पूरे नहीं होने के कारण लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो रही है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार शहरी जलापूर्ति योजना का लक्ष्य कबतक प्राप्त करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

सीमा राशि का भुगतान

23. श्री जितेन्द्र कुमार राय—स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 31 जुलाई, 2011 को प्रकाशित शीर्षक "क्षतिपूर्ति के भुगतान पर रोक" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2009 में खरीफ फसल के लिए राज्य के एक लाख 41 हजार 877 गैर-ऋणी किसानों का फसल बीमा एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी, नयी दिल्ली द्वारा किया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि फसल बीमा राशि 168.34 करोड़ का भुगतान तीन वर्षों से लम्बित होने के कारण किसानों की स्थिति दयनीय हो गयी है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अनहित में किसानों के फसल बीमा की राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पशु तस्करी का रोकना

24. श्री राम प्रवेश राय—क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रतिदिन हजारों की संख्या में पशुओं की तस्करी कर पं० बंगाल एवं असम के रास्ते बंगलादेश ले जाने का कार्य पशु तस्करों द्वारा किया जा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि इन पशुओं में हल जोतने वाले बैल एवं दुधारु गाय-भैंस की संख्या ज्यादा रहती है;

(3) क्या यह बात सही है कि थडल्ले से किये जा रहे इस पशु तस्करी से राज्य के संसाधनों एवं कृषि क्षेत्रों पर काफी बुरा असर पड़ रहा है;

(4) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन पशु तस्करों को विरुद्ध सख्त एवं कठोर कार्रवाई कर राज्य से बड़े पैमाने पर किये जा रहे पशु तस्करी को रोकने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 1 मार्च, 2012 (ई०) ।

लक्ष्मी कान्त झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।